(e) by when the final appraisal meeting is likely to be held and the agreement signed?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM IAKHAR) (a) to (e) A comprehensive Agriculture Development Project for Rajasthan is currently under preparation and discussion with the World Bank. The quantum of funding, time of likely assistance, details of area coverage, etc., would be known only after the project is finalised.

मेटल स्क्रेप का आयात

*440. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1991-92 में स्क्रेप के आयात के लिये मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन को 450 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि पिछले वर्षों के दौरान किये गये आवंटन की अपेक्षा कम है;

(ग) क्या अवमूल्यन के कारण आयात की मात्रा पिछले वर्षों की अपेक्षा कम होने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो इस कारपोरेशन द्वारा कितना स्क्रैप आयात किया गया और लघु इस्पात एककों की जरूरतों को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) यह सच है कि वर्ष 1991-92 में स्क्रैप का आयात करने के लिये वर्ष के आरम्भ में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे तथापित बाद में राशि को कम करके लगभग 150 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) अवमूल्यन और निर्बाध विदेशी मुद्रा का कम आबंटन करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में आयात की मात्रा में कमी होने की संभावना है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक एम०एस०टी०सी० के माध्यम से आयात के रूप में देश में 1,29,000 टन स्क्रैप प्राप्त हुआ। 79,000 टन के लिए भी एम०एस०टी०सी० द्वारा आर्डर दे दिए गए हैं। एम०एस०टी०सी० को उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा से यह लगभग 2,00,000 टन के और आर्डर दे सकती है। प्रयोक्ता उद्योगों (लघु इस्पात यूनिटों सहित) को एम०एस० टी० सी० द्वारा कारपोरेशन में पंजीकृत उनकी मांग के अनुपात में आयातित स्क्रैप का वितरण किया जाता है। वास्तविक प्रयोक्ता भी निर्यात-आयात पत्र के माध्यम से स्क्रैप का सीधे आयात कर सकते हैं।

New functions of NDDB

3301. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Dairy Development Board has sought a portion of private channels in order to launch a campaign against Government's decision to privatise Dairy Industry as reported in the "Times of India" dated the 11th October, 1991; and

(b) whether Government propose to allocate the present works of the National Dairy Development Board in relation to milk, fish, vegetable oils, fruits and vegetables, vaccines etc- to other relevant Boards to avoid duplication?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.